



कांग्रेस का संगठन क्यों चरमरा गया यू.पी. में, बिहार में?

इसका जवाब ढूंढने में ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, राजस्थान में नए जिलाध्यक्षों का चयन, इस पतन की कहानी समझने-समझाने के लिए पर्याप्त है

- रेणु मित्तल -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 25 नवंबर। के. सी. वेणुगोपाल के संरक्षण में और एआईसीसी प्रभारी रंधावा की सक्रिय भूमिका के साथ, राजस्थान कांग्रेस ने उस उदयपुर घोषणा पत्र को पूरी तरह नजरअंदाज़ कर दिया है, जिसे बड़े धूमधाम से इसलिए जारी किया गया था कि कांग्रेस पार्टी के कामकाज में सुधार लाने के लिए नई गाइडलाइंस लागू हों। जिले के अध्यक्षों की नियुक्ति में सभी नियमों और तय प्रक्रियाओं की अनदेखी की गई और पूरे काम को एक मज़ाक बना दिया गया। अजमेर ग्रामीण से विकास चौधरी, जो आरएसएस पृष्ठभूमि से आते हैं, उन्हें पार्टी में शामिल किया गया, विधानसभा चुनाव का टिकट दिया गया, वे विधायक बने और अब उन्हें जिला अध्यक्ष बना दिया गया है। चौधरी उन 12 विधायकों में से एक हैं, जिन्हें जिला अध्यक्ष बनाया गया है, किन्तु उदयपुर घोषणा में तय 5 साल की कूलिंग ऑफ़ अवधि का पालन किए बिना।

- उदाहरण के लिए, अजमेर में आरएसएस पृष्ठभूमि के विकास चौधरी को नया जिलाध्यक्ष बनाया है, कांग्रेस ने।
- चित्तौड़गढ़ में नया जिलाध्यक्ष उसे बनाया गया है, जिसे कांग्रेस से निष्काशित किया हुआ है तथा जिसकी विवादित पृष्ठभूमि पुलिस थानों के रिकॉर्ड में अच्छी तरह अंकित है।
- हनुमानगढ़ में, उस व्यक्ति को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो अभी कुछ समय पूर्व तक आम आदमी पार्टी का पदाधिकारी था।
- नीम का थाना में, वह आदमी नया जिलाध्यक्ष बनाया गया है, जिसे सरकारी नौकरी से रिटायर हुए अभी एक साल भी नहीं हुआ।
- जहाँ तक, नए खून को बढ़ावा देने के प्रयास का सवाल है, डीडवाना में उसी आदमी को नया जिलाध्यक्ष घोषित किया गया है, जो आठ साल से जिलाध्यक्ष है। दौसा में भी उस आदमी को नया जिलाध्यक्ष बनाया गया है, जो 15 साल से जिलाध्यक्ष चला आ रहा है।
- ऐसी अजीबोगरीब नियुक्तियाँ, एक दो नहीं, कई हैं।
- इन कारनामों से क्या कांग्रेस संगठन की जड़ें मजबूत होंगी, राजस्थान में।
- साथ ही ऐसी कहानी, यू.पी., बिहार, मध्य प्रदेश में भी होती आई है। अतः, संगठन की जर्जर अवस्था समझना कोई कठिन काम नहीं है।

पर्यवेक्षकों की सलाह के खिलाफ प्रमोद सिसोदिया को जिला अध्यक्ष जाकर पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा ने बनाया है। उन पर चित्तौड़गढ़ का

हिस्ट्रीशीटर होने का आरोप है और उन्हें (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मौसम विभाग ने कुछ सांत्वना दी दिल्ली निवासियों को

मौसम विभाग के अनुसार, इथोपिया में ज्वालामुखी फटने से उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड व चट्टानों के पार्टिकल्स के बादल से दिल्ली पर न्यूनतम असर होगा, प्रदूषण की दृष्टि से

- श्रीनंद झा -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 25 नवंबर। पहले से ही खतरनाक वायु गुणवत्ता के कारण सांस लेने में मुश्किल झेल रहे दिल्लीवासियों को सोमवार को एक और पर्यावरणीय चुनौती का सामना करना पड़ा, जो एक असामान्य कारण से आ खड़ी हुई है। इथियोपिया में हुए एक दुर्लभ ज्वालामुखी विस्फोट से उठे सल्फर डाइऑक्साइड और बारीक चट्टानी कणों से घरे घने राख के बादल रविवार रात दिल्ली तक पहुँच गए, जिससे यह आशंका बढ़ गई कि राजधानी के ए.क्यू.आई. लैवल पर खतरनाक असर पड़ सकता है। दिल्ली और आसपास के शहर बीते दिनों से जहरीली हवा से जूझ रहे हैं। मंगलवार को दिल्ली का ए.क्यू.आई.

- यह बादल इतनी ऊँचाई पर है कि वह गुजरात, राजस्थान होता हुआ, दिल्ली व पंजाब पहुँचेगा तथा चीन की ओर बढ़ेगा, पर, उसका असर रास्ते में पड़ रहे शहर पर नहीं पड़ेगा। लेकिन, हवाई यात्राएँ जरूर प्रभावित होंगी।

382 दर्ज हुआ, जबकि गाजियाबाद में 396, नोएडा में 397 और ग्रेटर नोएडा में 382 रहा। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, ए.क्यू.आई. 400 से ऊपर “गंभीर” श्रेणी में आता है। दिल्ली में सरकारी ऑफिस और प्राइवेट संस्थान सोमवार को लागू किए गए स्टेज-3 ग्रेप के तहत 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की

अध्यक्षता में हुई बैठक में चिंता जताई गई कि दिल्ली-एनसीआर में लगभग 37 प्रतिशत वाहन पुराने बी.एल.1 और बी.एस.3 उत्सर्जन मानकों का पालन करते हैं। अधिकारियों को इस पर तत्काल सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए। दिल्लीवासियों के लिए थोड़ी राहत यह है कि मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इथियोपिया की ज्वालामुखीय राख ऊपरी वायुमंडल में यात्रा कर रही है और इसका सतह के स्तर पर खास असर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

लॉरेंस बिश्नोई के नाम की जैकेट बेचते तीन गिरफ्तार

जयपुर, 25 नवंबर। कोटपूतली पुलिस की टीम ने कस्बे में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम का महिमामंडन करने वाली वस्तुएं बेचने वाले लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कोटपुतली-बहरोड़ एसपी देवेन्द्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि

- कोटपूतली पुलिस ने गैंगस्टर को महिमामंडित करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की।

कोटपूतली के सिटी प्लाजा से लॉरेंस बिश्नोई के नाम का प्रचार करने वाली जैकेट बेचते हुए, कृष्ण उर्फ गुड्डू (38), संजय सैनी (31) और सुरेशचन्द शर्मा (50) को गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों ही कोटपूतली क्षेत्र के निवासी हैं। इन गिरफ्तार आरोपितों के पास से 35 जैकेट जब्त की गई हैं।

बयान होने से पहले सरकारी गवाह बने आरोपी को जमानत नहीं

जयपुर, 25 नवंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने मानव अंग तस्करी और किडनी प्रत्यारोपण से जुड़े एक मामले में कहा है कि सरकारी गवाह बने आरोपी को तब तक जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता, जब तक कि निचली अदालत में उसके बयान दर्ज नहीं हुए हों। इसके साथ ही, अदालत ने मामले

- हाई कोर्ट ने किडनी प्रत्यारोपण मामले में बाँग्लादेश निवासी नुरुल इस्लाम पर निर्देश दिए।

में निचली अदालत को कहा कि वह चार सप्ताह में आरोपियों पर चार्ज फ्रेम करने के संबंध में निर्णय ले। वहीं, चार्ज फ्रेम होने की स्थिति में सबसे पहले याचिकाकर्ताओं के बयान दर्ज करें। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को छूट दी है कि वे निचली अदालत में बयान दर्ज होने के बाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका पेश कर सकते हैं। जस्टिस अनूप कुमार की एकलपीठ ने ये आदेश बांग्लादेश निवासी नुरुल इस्लाम व एक अन्य की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिये। अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जल्दी सुनवाई का मौलिक अधिकार नागरिकों के साथ-साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। अदालत ने कहा कि न्याय में देरी पीडित (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘अगर एक भी मुसलमान का नाम कटा तो मैं दिल्ली की सरकार का पत्ता कटवा दूंगी’

मुस्लिम (बाँग्लादेशी) वोट बैंक की नाराज़गी को बढ़ने से रोकने के लिए हताश ममता बनर्जी ने नए-नए वादे देने शुरू किए

- अंजन रॉय -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 25 नवम्बर। ममता बनर्जी पर मुस्लिम समुदाय का गुस्सा बढ़ रहा है, क्योंकि वे चुनाव आयोग को एस आई आर प्रक्रिया को रोकने में नाकाम रही हैं। इस नाराज़गी के बीच अब मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ सीधी लड़ाई छेड़ दी है। आज एक सार्वजनिक सभा में उन्होंने राज्य के मुसलमानों को सीधे संबोधित करते हुए कहा कि अगर उनके नाम मतदाता सूची से हटाए गए, तो वे यह सुनिश्चित करेंगे कि (भाजपा की) केन्द्र सरकार भी हटा दी जाए। उन्होंने केन्द्र के खिलाफ सीधे कदम उठाने की धमकी दी है। उनकी मुख्य नाराज़गी यह है कि एस आई आर प्रक्रिया अगले साल होने वाले राज्य चुनावों से पहले क्यों चलाई जा जा रही है। वे अब मांग कर रही हैं कि एस आई आर का काम दो-तीन

- जैसा कि विदित ही है, मुस्लिम (बाँग्लादेशी) वोट बैंक नाराज़ है, ममता बनर्जी से, क्योंकि ममता बनर्जी एसआईआर प्रक्रिया रूकवा नहीं पाईं, जैसा कि उन्होंने वादा किया था। एसआईआर में नाम कटने के डर से बाँग्लादेशी वापस बाँग्लादेश जाने लगे हैं, भारी संख्या में।
- ममता बनर्जी ने एक नया नारा दिया, “आई लव बाँलादेश”, फिर, क्योंकि बाँग्लादेश में ममता जी के लिए ज्यादा ममता नहीं, उन्होंने नारा बदला और कहना शुरू किया, बाँग्लादेश के लिए मेरा प्रेम बाँग्ला भाषा के कारण है।
- पर, सभी नारों के बावजूद, बात कुछ बन नहीं रही, मुस्लिम (बाँग्लादेश) वोट बैंक धीरे-धीरे खिसक रहा है और ममता बनर्जी की हताशा बढ़ती जा रही है।

वर्षों तक चले, ताकि अगला चुनाव निपट जाए। असल में, वे सत्ता में और मुख्यमंत्री के पद पर बनी रहना चाहती हैं। लेकिन अब हालात उनके लिए तूफानी हो गए हैं और एस आई आर पूरा होने पर, उन्हें खतरा साफ-साफ दिख (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भाजपा महाराष्ट्र का अनुभव कर्नाटक में दोहराने को तैयार है

भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आदि डी.के. शिवकुमार से संपर्क में हैं तथा अगर वे कांग्रेस छोड़कर, अपनी सरकार बनाना चाहते हैं तो भाजपा अपने 82 विधायकों के साथ, उस सरकार को बाहर से समर्थन दे देगी

- इस चर्चा ने जोर इसलिए पकड़ा, क्योंकि डी.के. शिवकुमार कुछ नाखुश से हैं कांग्रेस से, क्योंकि पुराने वादे के अनुसार, नवंबर से उनका मु.मंत्री बनने का वादा पूरा नहीं कर रहा, कांग्रेस का हाइकमान।
- कांग्रेस नये-नये बहाने ढूँढ रही है, शिवकुमार को मु.मंत्री न बनाने के लिए। नवीनन्त बहाना यह है कि कांग्रेस हाइकमान शीघ्र शुरु होने वाले संसद के सत्र की तैयारी में व्यस्त हैं तथा सत्र के बाद कर्नाटक के मसले पर गहराई से विचार होगा।

और दिल्ली में अलग-अलग मीटिंग की है। लेकिन, कांग्रेस के शीर्ष सूत्रों का कहना है कि हाइकमान सिद्धारमैया को पूरा कार्यकाल देने के पक्ष में है और फिलहाल नेतृत्व परिवर्तन का कोई विचार नहीं है। तथापि, शिवकुमार पार्टी नेतृत्व को

नरम पड़ गये थे और उन्होंने गांधी की, “सही समय का इंतजार” करने की बात मान ली थी। इस नई राजनीतिक हलचल के बीच, लगभग 25 कांग्रेस विधायक, जो शिवकुमार के करीबी माने जाते हैं, इन दिनों दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। कांग्रेस सूत्र इस घटनाक्रम को कम महत्व देते हुए कह रहे हैं कि ये विधायक नेतृत्व परिवर्तन के लिए दबाव नहीं डाल रहे, बल्कि लंबे समय से लंबित मंत्री पदों की मांग कर रहे हैं, जिस पर सन्निकट कैबिनेट विस्तार के समय विचार किया जा सकता है। इसी बीच, भाजपा इस पूरे घटनाक्रम पर कड़ी नज़र रखे हुए है। पिछले कुछ दिनों से पार्टी के भीतर राजनीतिक गतिविधियाँ तेज हुई हैं। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बिहार विधान सभा का पहला सत्र 1 दिसंबर से

पटना, 25 नवंबर। बिहार विधानसभा का पहला सत्र, हाल ही में संपन्न हुए चुनाव के बाद एक दिसंबर से प्रारंभ होगा। बिहार विधानसभा सचिवालय के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार,

- दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा।

विधानसभा सत्र के पहले दिन नव-निर्वाचित विधायकों को प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव शपथ दिलायेंगे। पहले दिन की कार्यवाही के बाद 2 दिसंबर को विधानसभा के नये अध्यक्ष का चुनाव सदन के सदस्यों द्वारा किया जायेगा, जिसके बाद सदन नियमित रूप से कामकाज करना शुरू कर देगा। इसके बाद 3 दिसंबर को बिहार के राज्यपाल अरिफ मोहम्मद खान, बिहार विधानमंडल के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद उसी दिन सरकार (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

“चीफ लोको इंस्पेक्टर” विभागीय पदोन्नति परीक्षा धांधली में एक आरोपी को राहत मिली

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि, लोकपाल ने जांच शुरू करने से पहले याचिकाकर्ता को अनिवार्य सुनवाई का अवसर नहीं दिया

नई दिल्ली/जयपुर (कासं)। पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा आयोजित “चीफ लोको इंस्पेक्टर” पद के लिए विभागीय पदोन्नति परीक्षा में हुई धांधली में दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी मुजाहत अली खान को राहत दी है। अदालत ने माना कि लोकपाल ने जांच शुरू करने से पहले आवश्यक कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया और याचिकाकर्ता को अनिवार्य सुनवाई का अवसर नहीं दिया था। याचिकाकर्ता मुजाहत की ओर से पैरवी राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच के प्रैक्टीशनर अधिवक्ता हितेश कुमार ने की थी।

जैसा कि विदित है कि पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा “चीफ लोको इंस्पेक्टर” पद के लिए विभागीय पदोन्नति परीक्षा 13 मई 2023 तथा

- ज्ञात रहे कि पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा “चीफ लोको इंस्पेक्टर” पद के लिए विभागीय पदोन्नति परीक्षा वर्ष 2023 में 13 तथा 17 मई को करवाई थी।
- इस परीक्षा को लेकर आरोप थे कि, रेलवे ऑफिसर्स ने घूस लेकर ओएमआर शीट में हेरफेर की और कुछ अभ्यर्थियों को पुनर्मूल्यांकन में लाभ पहुंचाया
- इस मामले में लोकपाल ने सी.बी.आई. को जांच सुपुर्द की थी, फिलहाल 5 अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच जारी रहेगी

17 मई 2023 को करवाई गयी थी। इसमें कुल 96 उम्मीदवारों ने भाग लिया था और परिणाम 15 सितंबर 2023 को जारी किए गए। बाद में 6 सितंबर 2024 को लोकपाल के

समक्ष शिकायत दर्ज की गई कि, इस परीक्षा में ओएमआर शीट में हेराफेरी की गई। शिकायत में आरोप यह भी लगाया गया था कि, रेलवे अधिकारियों ने रिश्तत लेकर कुछ

उम्मीदवारों को लाभ दिया और मूल्यांकन अधिकारी तथा उम्मीदवार के बीच संदिग्ध कॉल रिकॉर्ड पाए गए। लोकपाल ने इस मामले की प्राथमिक जांच सी.बी.आई. को सौंपी, जिसकी फॉरेंसिक जांच में सामने आया कि, ओ.एम.आर. शीट में वाकई हेराफेरी की गई थी। मूल्यांकन अधिकारी भी कुछ अभ्यर्थियों से फोन पर बातचीत करता था। इसके प्राथमिक जांच के बाद सीबीआई को विस्तृत जांच करने के आदेश दिए गए थे, जिसकी रिपोर्ट 9 सितंबर 2025 को लोकपाल को सौंपी गई। जिसमें पांच रेलवे अधिकारी, जिन्हें पहले लोकपाल ने सुनवाई के लिए बुलाया था, के अलावा मुजाहत अली खान को भी आरोपी बनाया और मुकदमा

दर्ज करने की सिफारिश की गई। लोकपाल ने पश्चिम मध्य रेलवे के प्रवर्तन अधिकारी को मुजाहत अली खान से उसका जवाब लेकर लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश दिए थे। परंतु इस कार्रवाई के बीच मुजाहत को एफ.आई.आर. में आरोपी घोषित कर दिया गया था। जिस पर आपत्ति करते हुए मुजाहत अली खान ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की थी। अदालत ने कहा कि, लोकपाल द्वारा जांच के आदेश वहां तक सीमित किए जाते हैं, जहां तक याचिकाकर्ता मुजाहत अली खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात की गई है। क्योंकि उससे पक्ष सुना नहीं गया है। परंतु शेष 5 आरोपियों के खिलाफ जांच जारी रहेगी।

आधुनिक तकनीक से लैस होगी राजस्थान पुलिस

अपराधियों की कुंडली निकालना अब होगा आसान

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर । राजस्थान पुलिस अब अपराध और अपराधी ट्रैकिंग में एक महत्वपूर्ण तकनीकी छलांग लगाने की तैयारी में है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध शाखा हवा सिंह घूमरिया के निर्देशन में राज्य की समस्त फील्ड यूनिट्स के लिए एनसीआरबी नई दिल्ली द्वारा एक गहन ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य पुलिस अधिकारियों को नवीनतम तकनीक और कानूनी उपकरणों से लैस करना है ताकि अनुसंधान की गुणवत्ता और गति बढ़ाई जा सके।

इस महत्वपूर्ण सत्र का संचालन एनसीआरबी, नई दिल्ली के डिप्टी डायरेक्टर आईजी जनमेजय खंडूरी और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा किया गया।

प्रशिक्षण में जिला पुलिस अधीक्षक, डीसीपी, अतिरिक्त पुलिस



पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध शाखा हवा सिंह घूमरिया के निर्देशन में राज्य की समस्त फील्ड यूनिट्स के लिए एनसीआरबी नई दिल्ली द्वारा गहन ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई।

अधीक्षक, वृत्ताधिकारी, थानाधिकारी, और सीसीटीएनएस ऑपरेटर सहित पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने भाग लिया।

पुलिस जांच को मिलेगी नई धार आईजी खंडूरी ने एनसीआरबी के

औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित भूखंडों का अनुमति उपयोग बदलवा सकेंगे आवंटी

जयपुर (कासं)। रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित भूखंडों पर एक अनुमत उपयोग से दूसरे अनुमत उपयोग की स्वीकृति निर्धारित शुल्कों पर प्रदान की जा सकेगी। इस आदेश के अंतर्गत इच्छुक पट्टाधारियों को आवेदन प्रस्तुत करने के लिए रीको का ईआरपी पोर्टल 26 नवम्बर 2025 को प्रातः 10 बजे से खोला जायेगा। ज्ञात रहे कि रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित भूखंडों की उपयोगिता और अधिक व्यावहारिक, पारदर्शी व समायुक्त बनाने के लिए “रीको भू-निपटान नियम, 1979 के परिपाम 20(सी)” के संवन्ध में निदेशक मण्डल ने 24 अक्टूबर 2025 को आदेश जारी किए थे। आदेश के मुताबिक, अब इच्छुक

- रीको प्रशासन के ईआरपी पोर्टल पर 26 नवंबर से आवेदन कर सकेंगे इच्छुक पट्टाधारी
- रीको की इस पहल से पट्टाधारियों को अतिरिक्त सुविधा तथा राज्य सरकार को राजस्व मिलेगा
- रीको प्रशासन की इस पहल से प्रदेश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा एवं नवीन रोजगारों का सृजन होगा

पट्टाधारी अपने भूखण्ड पर एक अनुमत गतिविधि से दूसरी अनुमत गतिविधि परिवर्तित करना चाहें तो वे अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से रीको ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन मय शुल्क

25 हजार रुपए तथा विहित दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों को परीक्षणोपरांत निर्धारित राशि जमा कराने पर एक अनुमत उपयोग/गतिविधि से दूसरे अनुमत उपयोग/गतिविधि की स्वीकृति

जारी की जा सकेगी। रीको भू-निपटान नियम, 1979 के नियम 20 (सी) के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों की निस्तारण "फर्स्ट कम फर्स्ट आउट (फोफो)" के सिद्धांत पर निर्णय किया जाएगा। विस्तृत नियम रीको की वेबसाइट पर उपलब्ध है। रीको की इस पहल से पट्टाधारी अपने भूखण्डों पर अन्य अनुमत गतिविधि का संचालन स्वीकृति के उपरान्त कर सकेंगे, जिससे न केवल उन्हें अतिरिक्त सुविधा प्राप्त होगी, बल्कि राज्य सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी भी होगी। इसके साथ ही इससे प्रदेश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा एवं नवीन रोजगारों का भी सृजन होगा।

अभ्यर्थियों को बैंक डेट की फर्जी डिग्री बेचने वाला बदमाश गिरफ्तार

पी.टी.आई. भर्ती परीक्षा फर्जीवाड़े मामले में एस.ओ.जी. ने 25 हजार रुपए का इनामी बदमाश दबोचा

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी)ने कार्रवाई करते हुए शारीरिक शिक्षक (पीटीआई) भर्ती परीक्षा-2022 में अभ्यर्थियों को बैंक डेट की फर्जी डिग्री बेचने के आरोप में 25 हजार रुपए का इनामी आरोपित रवि कुमार उर्फ रवि त्यागी को गिरफ्तार किया।

एसओजी की पृष्ठताछ में सामने आया कि आरोपित फर्जी डिग्री देने वाली निजी यूनिवर्सिटी में रेगुलर स्टूडेंट का नाम काटकर रुपए देने वाले का नाम जोड़ देते या खाली सीट पर ऐसे युवाओं का नाम भरकर फर्जी डिग्री बनवा देते थे। फिलहाल एसओजी की ओर से मांगने पर भी इन डिग्रियों का रिकॉर्ड मुहैया नहीं करवाया जाता है।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (एडीजी एसओजी) विशाल बंसल ने बताया कि आरोपित रवि त्यागी को नोएडा से पकड़ा गया। जो गिरफ्तारी से बचने के लिए देशभर के धार्मिक स्थलों पर छिपता रहा।

इस गिराह ने विभिन्न विश्वविद्यालयों के माध्यम से बैंक डेट की फर्जी डिग्रियां और अंकांतालिकाएं तैयार करवाकर हजारों छात्रों तक पहुंचाई है। इस मामले में ओपीजेएस विश्वविद्यालय चूरू और जेएस विश्वविद्यालय शिकोहाबाद उत्तर प्रदेश के चांसलर,संचालक,पूर्व रजिस्ट्रार

- आरोपित रवि त्यागी को पुलिस ने नोएडा से पकड़ा है, वह गिरफ्तारी से बचने के लिए देशभर के धार्मिक स्थलों पर छिपता रहा
- इस मामले में ओपीजेएस विश्वविद्यालय चूरू और जेएस विश्वविद्यालय शिकोहाबाद उत्तर प्रदेश के चांसलर, संचालक तथा पूर्व रजिस्ट्रार सहित कई आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

सहित कई आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

एडीजी बंसल ने बताया कि आरोपित रवि त्यागी जेएस विश्वविद्यालय शिकोहाबाद में नौकरी करते हुए फर्जी डिग्रियां बनवाने में मुख्य भूमिका निभाता। ओपीजेएस विश्वविद्यालय पर एसओजी की कार्रवाई की जानकारी लगते ही रवि त्यागी फरार हो गया था। रवि की गिरफ्तारी पर एसओजी ने 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। आरोपी के नोएडा में आने की जानकारी मिलने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी रवि ने ओपीजेएस विश्वविद्यालय से खुद के लिए लॉ में पीएचडी की डिग्री बनवा रखी है। इस डिग्री पर भी संदेह है। इसके आधार पर उसकी पीएचडी की डिग्री की भी जांच की जा रही है।

एडीजी ने बताया कि बैंक डेट में फर्जी डिग्रियां बेचने का खेल पीटीआई

भर्ती परीक्षा 2022 में तेजी से चला था। जहां अलग-अलग निजी विश्वविद्यालयों के संचालकों ने दलालों के जरिए हजारों छात्रों को बैंक डेट में फर्जी डिग्रियां बेची गईं। पीटीआई भर्ती 2022 में चयनित अभ्यर्थियों का फर्जीवाड़ा सामने आने पर एसओजी ने केस दर्ज कर जांच शुरू की और जांच के दौरान अलग-अलग विभागों की भर्तियों में भी फर्जी डिग्रियों से नौकरी हासिल करने की जानकारी सामने आई है।

फिलहाल फर्जी डिग्री जारी करने के मामले में एसओजी टीम जांच कर रही है। माना जा रहा है कि जांच के दौरान और कई खुलासे हो सकते हैं। गौरतलब है कि राजस्थान में सरकारी विभागों में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक,डमी अभ्यर्थी बिनाक परीक्षा पास कराने और फर्जी दस्तावेज के जरिए नौकरी हासिल करने के मामले में एसओजी की जांच लगातार जारी है।

अपात्रों को शिक्षक पद पर नियुक्ति देने पर रोक

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती-2021 में दो साल वाले डिप्लोमा से कम पात्रता रखने वालों को नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश मोहन सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता विश्वास शर्मा ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने 31 दिसंबर, 2021 को प्राइमरी और अपर प्राइमरी शिक्षकों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया। जिसमें अनिवार्य शर्त रखी गई कि अभ्यर्थी के पास प्राथमिक शिक्षा में दो साल का डिप्लोमा होना जरूरी है। याचिका में कहा गया कि पात्रता संबंधी विवाद को पूर्व में हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। वहीं इसके खिलाफ खंडपीठ में पेश अपील और सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी भी खारिज हो गई थी। ऐसे में यह पूर्व में ही तय हो चुका है कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए दो साल का बीएसटीसी डिप्लोमा होना जरूरी है। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार अब एक साल का प्रमाण पत्र रखने वाले अभ्यर्थियों को इस पद पर नियुक्त कर रही है। जबकि उनके पास दो साल की अवधि का बीएसटीसी डिप्लोमा भी नहीं है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार भर्ती विज्ञापन की शर्त में तय पात्रता की पालना सुनिश्चित करे और किसी भी अपात्र की भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाए।

जयपुर में 30 लाख से अधिक परिगणना प्रपत्र डिजिटल हुए

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जितेन्द्र सोनी ने 95 बीएलओ को किया सम्मानित

जयपुर (कासं)। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत परिगणना प्रपत्रों के डिजिटलीकरण कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जुझारू, सर्मापति एवं प्रेरक 95 बुध लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।

सम्मानित बीएलओ में दिव्यांग बीएलओ, पहली बार जिम्मेवारी संभालने वाले बीएलओ, सेवानिवृत्ति के निकट पहुंच चुके बीएलओ तथा वे

- विपरीत परिस्थितियों में भी लक्ष्य हासिल करने वाले बीएलओ प्रेरणास्रोत बने : डॉ. जितेन्द्र सोनी

जयपुर कलेक्ट्रेट में मंगलवार को उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ का सम्मान हुआ।

क्षेत्र के 23 बीएलओ, बस्सी विधानसभा क्षेत्र के 17 बीएलओ, आमेर विधानसभा क्षेत्र के 16 बीएलओ, शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के 10 बीएलओ, झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के 9 बीएलओ, दूदू विधानसभा क्षेत्र के 7 बीएलओ, जमवारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 6 बीएलओ, बारू विधानसभा क्षेत्र के 4 बीएलओ तो वहीं, चौमूं, फुलेरा एवं विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के 1-1 बीएलओ को सम्मानित किया गया।

इससे पूर्व भी विगत सप्ताह भी शत प्रतिशत डिजिटलीकरण का लक्ष्य हासिल करने वाले 4 बीएलओ को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सम्मानित किया गया था।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी मेघराज मोघाने बताया कि 30 लाख 75 हजार 806 यानी 63.77 फीसदी से अधिक परिगणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि बस्सी विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख 96 हजार 216, शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख 98 हजार 474, चौमूं विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख 9 हजार 42, चाकसू विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख 86 हजार 198, दूदू विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख 5 हजार 869, फुलेरा विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख 3 हजार 858, आमेर विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख 26 हजार 410, जमवारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख 77 हजार 526, हवामहल विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख 59 हजार 273 परिगणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख 11 हजार 53, आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख 50 हजार 658, झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख 48 हजार 346, बारू विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख 4 हजार 271, सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख 28 हजार 706, मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख 15 हजार 472, सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख 80 हजार 685 एवं विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख 73 हजार 749 परिगणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है।

अपूर्वा स्मार्टफोन एप से पेशेंट की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी संभव

जयपुर (कासं)। भगवान महावीर कैंसर अस्पताल की गाइनेकोलॉजिक ऑन्कोलॉजी विशेषज्ञ डॉ. अपूर्वा टाक ने केपटाउन में आयोजित इंटरनेशनल गाइनेकोलॉजिकल कैंसर सोसाइटी की ग्लोबल समिट में अपूर्वा स्मार्टफोन एप को प्लेनरी सेशन में प्रस्तुत किया। डॉ अपूर्वा एकमात्र भारतीय है जिन्हें यह मौका मिला। समीट में एप को साराहना करते हुए इसे मरीज-केंद्रित डिजिटल केयर के नए युग की शुरुआत बताया गया। राजस्थान की पहली एमसीएस एचयूसपरस्पेशलाइज्ड गाइनी ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ अपूर्वा ने बताया कि आज के समय में चिकित्सा क्षेत्र में एआई टूल्स और सर्जरी में रोबोटिक्स का उपयोग बढ़ रहा है, ऐसे में अपूर्वा एप मरीजों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह एप मरीजों को अपने लक्षणों और तकलीफों को परतला से रिकॉर्ड करने की सुविधा देता है। एप से प्राप्त डेटा को मरीजों के इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड (ईएमआर) से जोड़कर बीमारी और जीवन-गुणवत्ता से जुड़ा वास्तविक दुनिया का डेटा प्राप्त किया जा सकेगा। इससे उनकी रियल-टाइम मॉनिटरिंग, बेहतर संवाद और सही समय पर उपचार की शुरुआत का फायदा मिलने के साथ ही यह एप क्लीनिकल ट्रायल्स में डाटा संग्रह करने में भी सहायक होगा। अपूर्वा (ऑटो इलेक्ट्रॉनिक पेशेंट रिपोर्टेड आउटकम्स ऑन रियल टाइम वाया ईएमआर आमाल्यमेशन) को यूरोपियन सोसायटी ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी की गाइडलाइन के अनुसार तैयार किया गया है। डॉ अपूर्वा का चयन नेशनल कैंसर ग्रिड के प्रोग्राम इंटरनेशनल कोलोब्रेशन फॉर रिसर्च मैथडोलॉजी डवलपमेंट इन ऑन्कोलोजी में 2024 में हुआ था। इसके तहत डॉ अपूर्वा ने यह एपअंतरराष्ट्रीय मेंटर्स जिसमें अमेरिका के कालीस रॉड्रिगेज, कनाडा के क्रिस्टोफर बूथ, पेरिस के जेवियर पाओलेटी के साथ ही चेन्नई के ए. एस. रामकृष्णन के मार्गदर्शन में पूरा किया गया है।

लगजरी बस ने खड़े ट्रक को टक्कर मारी, दो की मौत, 20 यात्री घायल

दिल्ली से अहमदाबाद जा रही बस में 36 लोग सवार थे, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर हुआ हादसा

अलवर, (निर्स)। अलवर में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर लगजरी बस ने खड़े ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। बस का आगे का हिस्सा ट्रक के पिछले हिस्से में घुस गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का आगे का पूरा हिस्सा चकनाचूर हो गया। हादसे में बस कंडक्टर और ट्रक के खलासी की मौके पर ही मौत हो गई। बस और ट्रक के ड्राइवर समेत 20 लोग घायल हो गए।

जानकारी के अनुसार हादसा मंगलवार सुबह छह बजे पिनान कट के पास हुआ। दिल्ली से अहमदाबाद जा रही बस में 36 लोग सवार थे।

एक्सीडेंट के बाद हाईवे पर चीख-पुकार मच गई। पुलिस ने आसपास के लोगों की मदद से घायलों को बस से निकाला और एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचाया। बस में आगे के हिस्से में बैठे यात्रियों को ज्यादा चोट आई है।

राजगढ़ थाना प्रभारी राजेश मीणा ने बताया कि सुबह बस और ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था। इसमें दो लोगों की



टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का आगे का पूरा हिस्सा चकनाचूर हो गया।

मौत हुई है। कुछ घायलों को अलवर जिला अस्पताल तो कुछ को दूसरे हॉस्पिटल्स में भर्ती कराया गया है।

जानकारी के अनुसार, ट्रक का टायर पंचर हो गया था। खलासी टायर बदलने में लगा हुआ था। तभी

अचानक तेज रफ्तार बस ने ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। ट्रक खलासी हारुन पुत्र अब्दुल निवासी नूंह और

■ हादसे में बस कंडक्टर और ट्रक के खलासी की मौके पर ही मौत हो गई

■ ट्रक का पंचर टायर बदल रहा था खलासी, तभी बस ने ट्रक को टक्कर मार दी

लगजरी बस के कंडक्टर रोशन (30) निवासी कोटपुतली की मौके पर मौत हो गई। 20 घायलों को एम्बुलेंस से पिनान अस्पताल पहुंचाया, जहां से कुछ घायलों को गंभीर हालत में अलवर जिला अस्पताल लेकर गए। गंभीर घायल बस ड्राइवर विराट नगर निवासी भैरुराम को अलवर से जयपुर के लिए रेफर किया है। घायलों के परिजन भी हॉस्पिटल पहुंचे। ट्रक में लकड़ियां भरी हुई थीं।

कोलायत के गंगा सरोवर कैचमेंट एरिया में अवैध खनन गतिविधियों का ड्रोन सर्वे शुरू

बीकानेर, (निर्स)। खान विभाग ने बीकानेर के कोलायत क्षेत्र के गंगा सरोवर कैचमेंट एरिया में अवैध खनन के आकलन के लिए मंगलवार से ड्रोन सर्वे का कार्य शुरू कर दिया है। अवैध खनन गतिविधियों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा तकनीक के युग में अवैध खनन गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने के लिए ड्रोन जैसी नवीनतम तकनीक के उपयोग पर जोर देते रहे हैं। कोलायत के गंगासागर कैचमेंट एरिया में खनिज क्ले के अवैध खनन की जानकारी प्राप्त होते ही संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों की टीम बनाकर ड्रोन सर्वे के निर्देश दिए गए। ड्रोन सर्वे में माइनिंग व जियोलाॉजी विंग के वरिष्ठ अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाई गई है, जिससे पारदर्शिता के साथ तय समय-

- ड्रोन सर्वे में माइनिंग व जियोलाॉजी विंग के वरिष्ठ अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाई गई है
- अनुमान के अनुसार 70-75 हैक्टेयर क्षेत्र में ड्रोन सर्वे के माध्यम से अवैध खनन का आकलन किया जाएगा

सीमा में वास्तविक आकलन हो सके। प्रमुख सचिव खान एवं भूविज्ञान टी. रविकांत खान विभाग के अधीक्षण अभियंताओं सहित फील्ड अधिकारियों को अवैध खनन गतिविधियों पर सख्ती से कार्रवाई के साथ ही ड्रोन से सर्वे कराते हुए निगरानी रखने के निर्देश समीक्षा बैठकों में देते रहे हैं। कोलायत के गंगासरोवर कैचमेंट एरिया में अवैध खनन की जानकारी संज्ञान में आते ही ड्रोन सर्वे काराकर आकलन के निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों के क्रियान्विति में

अधीक्षण खनि अभियंता एनके बैरवा के मार्गदर्शन में मंगलवार से ड्रोन सर्वे आरंभ हो गया है। खनि अभियंता धीरज पंवार, वरिष्ठ भू वैज्ञानिक मनोहर सिंह राठौड़ व करणवीर सिंह द्वारा ड्रोन सर्वे विशेषज्ञों के साथ सर्वे कार्य शुरू कर दिया गया है। एक मोटे अनुमान के अनुसार 70-75 हैक्टेयर क्षेत्र में ड्रोन सर्वे के माध्यम से अवैध खनन का आकलन किया जाएगा। इसमें तीन से चार दिन का समय लगने की संभावना है। गौरतलब है कि

पिछले दिनों कोलायत के गंगा सरोवर कैचमेंट एरिया में खनिज क्ले आदि के अवैध खनन गतिविधियों की जानकारी प्राप्त हुई है। राज्य सरकार द्वारा प्रकरण संज्ञान में आते ही सख्त कदम उठाते हुए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई शुरू कर दी है।

ड्रोन सर्वे की रिपोर्ट प्राप्त होने पर वास्तविक अवैध खनन का आकलन हो पाएगा। इसके साथ ही रिपोर्ट का परीक्षण कर विभाग द्वारा संबंधित के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने सभी अधीक्षण खनि अभियंताओं व फील्ड अधिकारियों को अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई में किसी तरह की कोताही नहीं बरतने के निर्देश देने के साथ ही आधुनिक नवीनतम तकनीक के उपयोग के निर्देश दिए हैं।

बाइक चोरी मामले में तीन गिरफ्तार

पावटा, (निर्स)। विराटनगर थाना पुलिस ने बाइक चोरी कर खुर्द-बुर्द करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। साथ ही तीन शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पुलिस ने चोरी की गई बाइक के टुकड़े और अन्य संबंधित सामान भी बरामद किया है।

मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी सोहनलाल ने बताया कि 5 नवंबर को मैड निवासी पीडित सतीश कासलीवाल ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मैड पुलिस चौकी क्षेत्र के बाणगंगा स्थित कपासन माता मंदिर परिसर से बाइक चोरी का मामला दर्ज कराया था। इसके बाद मैड चौकी प्रभारी विनोद कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसने जांच शुरू की। टीम ने मंदिर परिसर के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान की। पुलिस ने महेंद्र मीणा पुत्र भरतलाल मीणा निवासी तेवड़ी और लोकेश गुर्जर निवासी सेवरा तन तेवड़ी को गिरफ्तार किया व सख्ती से पूछताछ करने पर पूरे मामले का खुलासा हुआ और एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हो सका।

अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार शीघ्र कराने की मांग की

अजमेर, (निर्स)। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 2023 के अंतर्गत वाणिज्य संकाय के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार अब तक आयोजित नहीं किया गया है, जिससे अभ्यर्थी भविष्य की लेकर चिंतित हैं। अन्य विषयों के साक्षात्कार 2024 में प्रारंभ किए जा चुके, किंतु वाणिज्य संकाय अब भी लंबित है। अभ्यर्थी एस.के. चौधरी द्वारा दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि इस भर्ती में 15 हजार से अधिक अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया था, जिनमें से लगभग 7,500 का साक्षात्कार हो चुका है। यदि प्रक्रिया में और देरी हुई तो चयन 2026 तक भी पूर्ण नहीं हो सकेगा, जिससे कॉलेजों में पद रिक्त रहेंगे। अभ्यर्थियों ने आयोग से नियमों एवं समयबद्ध साक्षात्कार आयोजित कर अंतिम परिणाम जारी करने की अपील की है।

जूनियर को चार्ज दिए जाने से आहत प्रो. रमेश बैरवा कॉलेज शिक्षा आयुक्त से मिले

- कॉलेज शिक्षा आयुक्त डॉ. ओमप्रकाश बैरवा को परिवेदना देकर संशोधित आदेश निकाल जारी दिए जाने की मांग की

सेवा में चयन वर्ष 1995 का है जबकि मेनावत 1998 के हैं। 2017 में जारी वरीयता सूची में प्रो मेनावत का स्थान 1506 पर है जबकि प्रो बैरवा का स्थान 159 पर है। अर्थात डॉ. मेनावत वरीयता में इनसे 1347 पायदान नीचे हैं।

आयुक्त को दिए प्रतिवेदन में प्रो. बैरवा ने लिखा है कि वरिष्ठता की खुली अनदेखी कर राजकीय महाविद्यालय गंगापूर सिटी का चार्ज इनसे छीनकर, तथ्यों की खुली अनदेखी कर प्रो. बनवारी लाल मेनावत को चार्ज दिए जाने के कॉलेज शिक्षा संयुक्त निदेशक के एचआरडी के नियम विरुद्ध, मनमाने आदेश से ये बुरी तरह आहत है। इन्हें घोर मानसिक पीड़ा हुई है। सामाजिक प्रतिष्ठा को बहुत ठेस पहुंची है।

पूर्वाग्रह की पराकाष्ठा है कि डॉ. मेनावत द्वारा खुद ही चार्ज लेने के उपरांत बनाए महाविद्यालय के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में जानबूझकर इनका नाम तक नहीं जोड़ा। इनका आरोप है

कि अनुसूचित जाति के प्रोफेसर के साथ किया गया यह भेदभाव एवं अन्याय संविधान और कानून की दृष्टि से तो और भी चिंताजनक है। राजकीय सेवा नियमों का ही नहीं, समानता के मौलिक अधिकार का खुला उल्लंघन है। राजस्थान विरवाविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ रूक्मटा डेमोक्रेटिक के प्रदेश संयोजक होने के नाते वैचारिक एवं जातिगत द्वेषतावश मिलभगत से इनके साथ किया उच्च शिक्षा के अधिकारियों का यह मनमाना, साजिशन कृत्य प्रतीत होता है।

प्रो. रमेश बैरवा ने प्रतिवेदन में यह भी लिखा है कि 20.11.2025 को महाविद्यालय कार्यालय समय के पश्चात रात्रि करीब 8 बजे प्रो. बनवारी लाल मेनावत इनकी अनुमति के बिना जबरन महाविद्यालय में घुसे। इनके साथ राजकीय महाविद्यालय वजीरपुर के नोडल अधिकारी संस्कृत सह आचार्य रामकेश मीना, राजनीति विज्ञान के

सहायक आचार्य धर्मवीर मीना एवं अन्य लोग भी थे। इन्होंने इनकी अनुमति के बिना अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी राधेश्याम गुर्जर जो कि हार्ट के मरीज हैं पर दबाव बनाकर जबरन

हिस्सेच रजिस्टर एवं अन्य कागजात लिए। संविदाकर्मों विजय गुप्ता पर भी दबाव बनाकर पत्र टाइप एवं अन्य कार्य करवाए। कागज फाड़े। सरकारी दस्तावेजों से छेड़छाड़ की। प्राचार्य कक्ष तक खोलकर आचार्याधिक कृत्य किया। रात के 10 बजे बाद तक महाविद्यालय में रहे। आयुक्तालय के आदेश बारे में प्रो. मेनावत ने इन्हें किसी भी तरह से प्रतिवाद नहीं किया। आदेश इन्हें व्हाट्सएप पर भी नहीं भेजा। अनाधिकृत रूप से इन लोगों के महाविद्यालय में घुसकर नियमविरुद्ध कृत्य की सूचना उचित कार्यवाही हेतु इन्हें मजबूरन आयुक्त कॉलेज शिक्षा, संयुक्त निदेशक एवं पुलिस में देनी पड़ी। प्रो बैरवा की एतित भी कि इस अवधि में यदि कोई अग्रिय घटना घटित हो जाती तो जिम्मेदारी तो कार्यवाहक प्राचार्य के तौर पर इन पर ही थोपी जाती। पूर्व में इस महाविद्यालय में चोरी एवं अग्रिय घटनाएं हो चुकी हैं।

कोटा मंडल से गुजरने वाली विशेष ट्रेनों की संचालन अवधि बढ़ाई

- सर्दियों के दौरान बढ़ते यात्री दबाव को ध्यान में रखते हुए विशेष ट्रेनों की अवधि को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है

2025 तक 04 टिप के लिए विस्तारित किया गया है, गाड़ी संख्या 09622 बांद्रा टर्मिनस-अजमेर साप्ताहिक एक्सप्रेस (सोमवार) को 08 दिसम्बर 2025 से 29 दिसम्बर 2025 तक 04 टिप के लिए विस्तारित किया गया है, गाड़ी संख्या 09625 अजमेर-दौंड साप्ताहिक एक्सप्रेस (गुरुवार) को 04 दिसम्बर 2025 से 25 दिसम्बर 2025 तक 04 टिप के लिए विस्तारित किया गया है। गाड़ी संख्या 09626 दौंड-अजमेर साप्ताहिक एक्सप्रेस (शुक्रवार) को 05 दिसम्बर 2025 से

26 दिसम्बर 2025 तक 04 टिप के लिए विस्तारित किया गया है, गाड़ी संख्या 09627 अजमेर-सोलापुर साप्ताहिक एक्सप्रेस (बुधवार) को 03 दिसम्बर 2025 से 31 दिसम्बर 2025 तक 05 टिप के लिए विस्तारित किया गया है, गाड़ी संख्या 09628 सोलापुर-अजमेर साप्ताहिक एक्सप्रेस (गुरुवार) को 04 दिसम्बर 2025 से 01 जनवरी 26 तक 5 टिप के लिए विस्तारित किया गया है।

कोहरे के कारण 4 पैसेंजर गाड़ियां निरस्त : घने कोहरे के चलते सुरक्षित संचालन की दृष्टि से कोटा मंडल से होकर गुजरने वाली गाड़ी संख्या 51907 ईदगाह-भरतपुर पैसेंजर, गाड़ी संख्या 51908 भरतपुर पैसेंजर, गाड़ी संख्या 51909 ईदगाह-भरतपुर पैसेंजर, गाड़ी संख्या 51910 भरतपुर-ईदगाह पैसेंजर गाड़ियां 1 दिसम्बर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक निरस्त रहेंगी।

अलवर जिला अस्पताल में निरीक्षण के दौरान टीम के अधिकारी हुए नाराज



अलवर जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में राजमेश की टीम निरीक्षण करने पहुंची।

अलवर, (निर्स)। अलवर जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में मंगलवार को राजमेश की टीम औचक निरीक्षण करने पहुंची। निरीक्षण में पता चला कि 7 में से केवल 3 ऑपरेशन टेबल चालू है, बाकी 4 टेबल सिविल कार्य के चलते बंद है। इस कारण आधे ऑपरेशन भी नहीं हो पा रहे हैं, जिससे आमजन को बड़ी परेशानी हो रही है।

जिला अस्पताल में जारी सिविल कार्य के कारण अगले तीन महीने तक यही हाल रहने का अनुमान है। राजमेश से एसोसिएट प्रो. गुरुशरण पुरी के नेतृत्व में टीम ने ऑपरेशन थिएटर की

- सात में से केवल तीन ऑपरेशन टेबल चालू मिली, तीन महीने का अल्टीमेटम

स्थिति की समीक्षा की। जहां सिविल कार्यों के चलते सभी ऑपरेशन टेबलों पर कार्य संभव नहीं हो पा रहा था। केवल तीन टेबलों पर ही ऑपरेशन हो रहे हैं, जिसे लेकर डॉ. पुरी ने गहरी नाराजगी जताई।

डॉ. पुरी ने बताया कि मरम्मत और निर्माण कार्यों के कारण ऑपरेशन

थिएटर की क्षमता पर सीधा असर पड़ा है, जिससे आमजन को समय पर उपचार नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने इस स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुनील चौहान को तीन महीने का समय दिया है। इसके अलावा अस्पताल परिसर में चल रहे सिविल कार्यों में देरी को लेकर भी राजमेश टीम ने चिंता व्यक्त की। सार्वजनिक निर्माण विभाग और इलेक्ट्रिक विभाग को निर्माण और मरम्मत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि चिकित्सा सेवाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

